इकाई 15 सुशासन उपागम*

इकाई की रूपरेखा

15.0 उद्देश्य

15.1 प्रस्तावना

15.2 सरकार से शासन तक

15.3 शासनः अवधारणा व लक्षण

15.4 सुशासन की विशेषताएँ

15.5 सुशासन से आगे

15.6 सुशासनः मुद्दे व चुनौतियाँ

15.7 निष्कर्ष

15.8 शब्दावली

15.9 संदर्भ लेख

15.10 बोध प्रश्नों के उत्तर

15.0 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद, आप निम्न को समझ सकेंगेः

- राज्य एवं सरकार की अवधारणा का अर्थ एवं दोनों में अंतर;
- सरकार से प्रशासन में संक्रमणकाल का परीक्षण;
- प्रशासन व सुशासन की अवधारणा व महत्व;
- सुशासन की विशेषताएं; तथा
- सुशासन के सम्मुख मुद्दे व चुनौतियाँ।

15.1 प्रस्तावना

सुशासन की अवधारणा को समझने के लिए आवश्यक है कि हम राज्य के विस्तृत अवधारणा को जानें, जो कि सरकार एवं शासन को सम्मिलित करता है। सरकार राज्य का एक महत्वपूर्ण भाग है, जिसके माध्यम से राज्य अपने लक्ष्य व उद्देश्यों को प्राप्त करता है। सामान्य शब्दों में शासन का आषय निर्णय निर्माण की प्रक्रिया एवं उसके क्रियान्वयन से है। इसकी प्रकृति व्यापक है तथा इसके सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक आयाम है। एक प्रक्रिया के रूप में भी यह व्यापक है। जिसमें सरकार के साथ निजी उपक्रम एवं नागरिक समाज के संगठन शामिल है। यह राज्य की संपूर्ण जिम्मेदारी है कि नागरिकों के जीवन की प्रक्रिया के द्वारा राज्य समाज में रहन सहन का उपयुक्त वातावरण, न्याय व्यवस्था का निर्माण, सामाजिक न्याय एवं समानता को स्थापित करने का प्रयास करता है। मुक्त नीति निर्माण, विधि का शासन, पारदर्शी प्रक्रिया, उत्तदारी ढाँचे तथा सशक्त नागरिक समाज के साथ शाासन की प्रक्रिया से सुशासन होता है।

**योगदानः* प्रो. उमा मेडुरी, लोक प्रशासन संकाय, सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ, इग्नू

पिछले दो दशकों में राज्य के ढाँचे तथा गतिशीलता में व्यापक सुधार देखने को मिले है। राज्य, समुदायों तथा सरकार के आंतरिक व बाह्य उत्तरदायित्वों के भागों से संबंधित मामलों के राजनीति, आर्थिक व शासन पर वैश्विक प्रभाव असाधारण रहा है एवं बदलाव की ओर अग्रसर रहा है। जैसा कि इकाई 13 ने नवीन लोक प्रबंधन में चर्चा की है कि वैश्विक स्तर पर संरचनात्मक सुधार व पुनः सामंजस्य हो रहा है। नागरिक भी स्वंय के अधिकार व उत्तरदायित्वों के प्रति जागरूक हो रहे है। उनकी अपेक्षाओं के स्तर में बढ़ोतरी हो रही है, जिसके परिणामस्वरूप सुशासन की आवश्यकता अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है। इस इकाई में हम राज्य सरकार की अवधारणा तथा सरकार के कार्यों की बदलती हुई प्रकृति पर चर्चा करेंगे, जिसने राष्ट्र को 'शासन से प्रशासन' की ओर परिवर्तित कर दिया है। सुशासन की अवधारणा तथा महत्व एवं विशेषताओं के बारे में विस्तृत चर्चा इस इकाई में की जाएगी। सुशासन को बढ़ावा देने में आने वाली चुनौतियों व प्रमुख मुद्दों पर भी चर्चा केन्द्रित की जाएगी।

15.2 सरकार से शासन तक

समुदाय राज्य की सीमाओं के अंतर्गत कार्य करता है। राज्य एक राजनीतिक संस्था है, जिसका निश्चित भूभाग तथा संप्रभु क्षेत्राधिकार होता है, तथा संसद, न्यायपालिका नौकरशाही आदि स्थाई संस्थाओं के द्वारा सत्ता का प्रयोग करता है। सरकार राज्य व समाज की महत्वपूर्ण संस्था है एवं सेवा व उत्पादन और सुविधा के लिए जिम्मेदारी है। उचित नीतियों व कार्यक्रमों के आधार पर निष्पक्षता को सुनिश्चित करने के लिए राज्य उत्तदायी होता है, जिससे वह निजी उपक्रम की गतिविधियों को नियंत्रित कर सके। जैसा कि हमने पूर्व में बताया सरकार को कई व्यापक कार्य सौपें गए है। कई देशों में इन कार्यों को करने के लिए सरकारों के द्वारा व्यवस्थित नियोजन किया गया है, तथा बहुत से उपक्रमों को मुनाफा कमाने के लिए स्थापित किया गया है। उदाहरण के लिए भारत में स्वतंत्रता पश्चात् नागरिक विमानन (Civil Aviation), कोयला, स्टील आदि क्षेत्रों में निजी क्षेत्रों के उपक्रमों को स्थापित किया गया। इसमें स्टील अथारिटी आफ इंडिया, तेल व प्राकृतिक गैस आयोग आदि शामिल है। परंतु समय के साथ सरकार की गतिविधियों इतनी बढ़ गई हैं कि मुद्रा–स्फीति, राज्य सरकार के उपक्रमों में बढ़ता खर्च, राजस्व में कमी आदि जैसी कई समस्याओं में बढ़ोतरी होती गई है। सामान्य रूप से सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के प्रति जनता का असंतोष बढ़ रहा है। सेवा प्रदान करने की वैकल्पिक व्यवस्था पर विचार किया जाने लगा है। इन सब गतिविधों से ऐसा समझा जाने लगा है कि सरकार को सेवाओं की प्रत्यक्ष उपलब्धता से हटना चाहिए तथा नीजी उपक्रमों को व्यापक क्षेत्रों में आने देना चाहिए। निजी बाजार (Sectors) सक्षम माने जाते हैं, क्योंकि वे प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देते हैं तथा लोगों को प्रभावी व त्वरित सेवाएं प्रदान करते हैं।

वैश्वीकरण का बढ़ता हुआ प्रभाव, एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है, जिसके हम साक्षी हैं। वर्तमान में आर्थिक स्थितियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहा है। विकास जैसे कि सोवियत संघ का विघटन, राजनीतिक, आर्थिक, सैन्य जैसे विभिन्न क्षेत्रों में अमरीका का बढ़ता हुआ प्रभुत्त, दूरसंचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी का प्रसार व्यापार, व्यापार से प्रतिबंधों को हटाना, पूंजी निवेश एवं बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन ने सरकारी कार्यप्रणाली पर दबाव बनाना शुरू कर दिया । नवीन लोक प्रबंधन के इकाई 13 में हमने इसके बारे में विस्तृत चर्चा की है।

महत्वपूर्ण क्षेत्रों में राज्य की भूमिका पर अनेक प्रश्न उठ रहे हैं, क्योंकि सरकार कुछ प्रमुख क्षेत्रों को सभांलने में नाकाम रही है। अतः सरकार को कुछ प्रमुख क्षेत्रों से हटना पड़ा है, जो कि प्रमुख सेवाओं को उपलब्ध कराती रही है। इससे निजी उपक्रमों एवं नागरिक

सामाजिक संगठन के रूप में जनता के पहल को मौका मिला की वो अपने कार्यक्षेत्र को वृहद् बनाये। उदाहरण के लिए भारत में निजी क्षेत्रों एवं जन संगठनों के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। राजस्थान के तरूण भारत संघ के राजेन्द्र सिंह को मैगसेसे अवार्ड (Magsaysay Award) सूखे की स्थिति से निपटने हेतु वर्षा जल संरक्षण तकनीक (Rain Water Harvesting Technique) का प्रयोग करने के लिए दिया गया। प्रतिकूल परिस्थितिग्रस्त क्षेत्रों के उन्नयन के लिए टाटा व इनफोसिस जैसे प्रतिष्ठान कार्य कर रहे हैं। ऐसे कई पहल है, जो कि गति एवं मान्यता प्राप्त कर रहे हैं।

लोक प्रशासन की कार्यप्रणाली, जो कि अब तक सरकार के प्रभुत्व में थी, उसका स्थान सरकार, बाजार तथा नागरिक समाज के लोगों के आपसी सहयोग से स्थापित तंत्र ने ले लिया है। प्रशासन के संकीर्ण विचारों में थोड़ा परिवर्तन हुआ है, जो कि पूर्णतया नौकरशाही पर आधारित था और पदसोपान व नियम तथा कानूनों पर जोर देता है एवं नागरिक केवल वस्तु व सेवा संबंधी नेटवर्क के निष्क्रिय स्वीकार कर्ता या प्राप्तकर्ता, सरकार, बाजार तथा नागरिक समाज जैसे हितधारको के साथ हो जाते हैं। प्रशासन वर्तमान में केवल गवर्नर केन्द्रित ही नहीं रह गया है बल्कि शक्ति व सत्ता गवर्नर से प्रशासक की ओर स्थानांतरित हो रही है। प्रशासन सीमाओं का भेद समाप्त हो रहा है, जिसमें सरकार का नियंत्रण कम हो रहा है। प्रशासन का वर्तमान सिद्धांत सरकार के विभिन्न भागों से पारस्परिक संपर्क तथा पारस्परिक स्वीकार्य निर्णयों पर आधारित आर्थिक व्यवसाय पर बल देता है। हम प्रशासन के महत्व, सिद्धांत एवं विशेषताओं की चर्चा अगले भाग में करेंगे।

15.3 शासनः अवधारणा व लक्षण

वर्तमान में विकास का पूर्णतावादी परिप्रेक्ष्य उपयोग में आ रहा है। पूर्व में जिसे किसी देश के द्वारा प्राप्त आर्थिक विकास कहा गया, उसका वर्तमान में ऐसे वातावरण का महत्वपूर्ण निर्माण करना है, जिसमें जनता उपयोगी जीवन जी सके। किसी भी देश की संपदा उसकी जनता है। अतः प्रशासनीय व्यवस्था तथा प्रक्रिया जो कि जनता के विकास को प्रोत्साहन देती है, वह ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे कि पूर्व के भागों में चर्चा की जा चुकी है कि प्रशासन शब्द का वृहद् अर्थबोध उपस्थित हो चुका है। इस भाग में हम प्रशासन के सिद्धांत के उद्भव तथा महत्व और विशेषताओं की चर्चा करेंगे।

तकनीकी दृष्टि से प्रशासन शब्द ग्रीक शब्द कायर्बनान (Kybernan) से लिया गया है एवं जिसका अर्थ है ''अनुकरणीय व मार्गदर्शक या वस्तुओं के नियंत्रण में'' 1970 के मध्य में हरलन क्लीवलैण्ड (Harlan Cleveland) द्वारा इसका प्रथम उपयोग किया गया, जब उन्होंने कहा कि जनता को कम सरकार एवं ज्यादा प्रशासन चाहिए। उन्होंने इसका उपयोग लोक व निजी संगठनों तथा बहुसंगठनात्मक व्यवस्थाओं के मध्य विशिष्टता को धुंधला करने में किया गया है। बाद के वर्षों में इस ने जटिल अर्थबोध उपस्थित किए हैं।

कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे विश्व बैक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आदि के द्वारा खास तौर पर विकासशील देशों के विकास के प्रोत्साहन के लिए वित्तीय सहायता में संलग्न है। 1980 के दशक में इनके द्वारा दी गई वित्तीय सहायता की अन्य शर्तें थी, जिन्होंने विकासशील देशों को व्यापार रूकावटों को कम या समाप्त करने पर बल दिया, अनुदान को हटाना व मूल्य नियंत्रण, सामाजिक कल्याण के प्रावधानों को कम करना, लोक व राज्य आधारित उपक्रमों के व्यापारिक कार्यों का निजीकरण, विभिन्न क्षेत्रों में बाजार आधारित विचारों को प्रोत्साहन देना एवं प्रतियोगिता को बढ़ावा देना आदि शामिल है। वित्तीय सहायता को बाजार आधारित सुधार से जोड़ा गया है, जो इन देशों से अपेक्षित था। भारत भी उन देशों में शामिल हैं जिसने 1991 में इन उपायो को क्रियान्वित करने का प्रयास किया।

सुशासन व प्रशासन के सिद्धांत की चर्चा से पूर्व वैश्वीकरण के परिणामस्वरूप विश्वव्यापी सुधारों के विभिन्न चरणों को जानना आवश्यक है। पहले चरण के सुधारों को पहले युग के सुधार माना गया है, जो कि 1980 के वर्ल्ड बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के द्वारा दिए गए सुधार कार्यक्रमों से संबंधित था । ये खासतौर पर इस समय काल में विकासशील देशों द्वारा अनुभव किए गए आर्थिक संकट के लिए था। इन सुधारों में मुक्त व्यापार, बाजार का नियंत्रण मुक्त होना आदि है।

इस के बाद द्वितीय युग के सुधार प्रशासन के रूप में है। समय के साथ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा यह जानने में आया कि बाजार प्रभावित सुधार को लागू करने पर अपेक्षित परिणाम नहीं मिले, तथा कई देशों में विकास दर आशा से काफी कम था। इस कारण से ही विश्व बैंक ने 1989 में अपने परीक्षण व विश्लेषण को प्रकाशित किया, जो कि उसके उपसहारा अफ्रीका के अनुभव थे। बैंक ने ''उप सहारा अफ्रीकाः संकट से संपोशित विकास तक '' (Sub-Sahara Africa: from Crises to Sustainable Growth) दस्तावेज प्रकाशित किया, कुछ प्रमुख कारकों का वर्णन किया, जो बाजार प्रभावित सुधारों के क्रियान्वयन के लिए मददगार साबित हो। इसका प्रमुख कारण लोक व सरकारी संस्थाओं की अपने कार्यों को प्रभावी व सक्षम रूप से करने में असफलता है।

अतः बैंक ने सर्वप्रथम प्रशासन को महत्व देने की आवश्यकता पर बल दिया है। उनकी व्याख्या के अनुसार प्रशासन के चार प्रमुख भाग हैः

1) सार्वजनिक क्षेत्र प्रबंधन (Public Sector Management)
2) उत्तरदायित्व (Accountability)
3) विकास का कानूनी ढाँचा (Legal Framework for Development)
4) पारदर्शिता तथा सूचना तक पहुँच (Transparency and Information Accessibility)

इन भागों के आधार पर प्रशासन से मुख्यतया तात्पर्य कानूनी ढाँचे में सरकारी एजेन्सियों द्वारा नीतियों का निरूपण व क्रियान्वयन है। जनता को उचित जानकारी मिलने, व्यवस्था में खुलापन एवं राजनीतिज्ञों, नौकरशाह या अफसरों के उत्तरदायित्व पर बल देता है।

किसी भी राजनीतिक व्यवस्था के लिए प्रशासन आवश्यक है, क्योंकि इसमें नीतियों का क्रियान्वयन होता है, जो कि जनता को प्रभावित करती है। प्रशासन संविधान के तीन स्तंभों कार्यपालिका, व न्यायपालिका पर निर्भर है। व्यवस्थापिका कानून का निर्माण करता है, कार्यपालिका (राजनीतिक व स्थायी) कानून का क्रियान्वयन एवं न्यायपालिका कानून की व्याख्या करती है। उदाहरण के लिए स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा, धन के संसाधन एवं जनता के लिए ढाँचा व सुविधाओं के लिए प्रभावी प्रशासन की आवश्यकता है।

अब तक यह स्पष्ट हो चुका होगा कि प्रशासन के सिद्धांत का तात्पर्य वह प्रक्रिया या मशीनरी है, जो कि नीति निर्माण व क्रियान्वयन से संबंधित है एवं प्रकृति काफी वृहद् होती है। इसके अंतर्गत सरकार, निजी उपक्रम तथा पूर्ण रूप से स्थापित समुदाय आते हैं। उदाहरण के लिए सरकार सबके लिए शिक्षा की नीति पर कार्य करना चाहती है। इस नीति को केवल सरकार ही कार्यरूप में परिणत कर सकती है, परंतु क्रियान्वयन में सामूहिक प्रयास आवश्यक है। प्रशासन मुख्यतया संयुक्त प्रयासों को बढ़ावा देने एवं सरकार, बाजार तथा लोगों के साथ कार्य करता है। इसका मुख्य उद्देश्य अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख है, जिसे केवल सरकार के माध्यम से ही प्राप्त नहीं किया जा सकता है, बल्कि सरकारी व निजी संगठन और नागरिक समाज संगठन के सहयोग की आवश्यकता होती है। अब हम सुशासन के सिद्धांत व प्रमुख विशेषताओं की चर्चा करेंगे।

15.4 सुशासन की विशेषताएँ

कई देशों में प्रशासन संबंधी समस्याओं को अधिक महत्वपूर्ण नहीं समझा गया कि वे विकासात्मक प्रक्रिया में रूकावट बनेगी। वाशिंगटन सहमति (Washington Consensus) ने भी राज्य की संस्थाओं के सुधार पर अधिक बल नहीं दिया एवं नीति निर्माताओं को बाजार प्रभावी व्यवस्था में अपनी भूमिका निभाने के लिए मदद की है। धीरे धीरे दान देने वाली एजेंन्सियों ने यह स्वीकारा की प्रशासन के मुद्दे अनवरत विकास व व्यवस्थित रूपांतरण (Sustainable Development and Systematic Transformation) के लिए महत्वपूर्ण है एवं अनुदान संबंधी नीतियों में शामिल करने की उन्हें आवश्यकता भी है। बहुपक्षीय एजेंन्सियों ने अनुदान के लिए प्रावधान की शुरूआत की जो कि देशों की शासन व्यवस्था की उन्नति से जुड़ी है।

जैसा कि पूर्व के भागों में चर्चा की गई है कि विश्व बैंक ने प्रशासन की अवधारणा को सर्वप्रथम अपनी रिपोर्ट ''Sub-Sahara Africa: From Crisis to Sustainable Growth (1989) में प्रस्तुत किया था। इस रिपोर्ट में बैंक ने क्षेत्र के संकट को ''प्रशासन का संकट'' बताया था। बैंक ने बढ़ते हुए भ्रष्टाचार, राजनीतिक शाक्ति के व्यक्तिगत उपयोग, मानव अधिकार की उपेक्षा, गैर उत्तरदायित्व व गैर निर्वाचित सरकार की दृढ़ता को संघारणीय विकास का प्रमुख तत्व माना है। प्रशासन का संकट ढाँचागत सामंजस्य कार्यक्रम की क्षमता में कमी के लिए उत्तरदायी था।

धीरे-धीरे विश्व बैंक ने प्रशासन के कार्यक्रम (Agenda) को कुछ विशेषताओं के आधार पर वृहद बनाया एवं उसे सुशासन बताया है। विश्व बैंक (1992) ने ''प्रशासन व विकास'' नामक अपने प्रलेख में प्रशासन की व्याख्या ''देश के विकास के लिए, देश के आर्थिक व सामाजिक संसाधनों के प्रबंधन के लिए शक्ति के उपयोग के तरीके'' के रूप में की है। प्रशासन निर्भर करता हैः (क) राजनीतिक व्यवस्था के रूप में (संसदात्मक, अध्यक्षात्मक, सैन्य, नागरिक, लोकतांत्रिक अथवा सर्वाधिकारवादी) (ख) वह प्रक्रिया जिसमें देश की आर्थिक व सामाजिक संस्थानों के प्रबंध के लिए सत्ता का उपयोग किया जाता है (ग) नीति निर्धारण, निर्माण व क्रियान्वयन में सरकार की क्षमताा। कानून के गलत क्रियान्वयन, क्रियान्वयन में देरी, सही लेखा प्रणाली की अनुपस्थिति, उपलब्धता में कमी जिसके कारण भ्रष्टाचार में बढ़ोतरी, सार्वजनिक निवेश की प्रमुखता में विकृति, परियोजनाओं के निर्माण व क्रियान्वयन में हितग्राहिया के समावेश में असफलता , जैसे कुछ प्रमुख प्रशासन संबंधी समस्याओं को बैंक ने रेखांकित किया है। बैंक ने खराब प्रशासन के लक्षण भी बताए हैं। कानून व सरकार के पूर्वानुमानित ढाँचे की स्थापना की असफलता, जो कि विकास एवं नियामक नियमों में सहायक है और बाजार की कार्यप्रणाली को बाधित कर रहा हो, व निर्णय निर्माण को अपारदर्शी बनाता हो, ऐसे कुछ लक्षण इसमें शामिल किए गए है।

विश्व बैंक सुशासन को भविष्यावाणी, नीति निर्माण की प्रबुद्धता व खुलापन, व्यवसायिक लोकाचार से ओत प्रोत नौकरशाही, जनता की लोकप्रियता से संबंधित, विधि का शासन, पारदर्शी प्रक्रिया व सार्वजनिक कार्यों में भागीदारी करता हुआ सशक्त नागरिक समाज आदि से संबंधित माना है। भागीदारी अर्थात् सुशासन की आवश्यकता, जो कि आर्थिक, मानवीय, संस्थात्मक विकास के आवश्यक है। इसके लिए नागरिकों के प्रयास जरूरी है। सुशासन के चार आयामों पर बल दिया गया है ये हैं – (अ) सार्वजनिक क्षेत्र प्रबंधन (क्षमता व दक्षता) (ब) उत्तरदायित्व (स) विकास के लिए विधिक ढॉचा (द) सूचना व पारदर्शिता। विश्व बैंक ने सुशासन के कुछ प्रमुख आधार बताए हैं जो कि निम्न हैः

- विधि के शासन का संचालन : इसके अंतर्गत पर्याप्त कानून आवश्यक है, जो कि व्यैक्तिक सुरक्षा तथा बाजार के क्रियान्वयन पर ध्यान दें। यह स्वतंत्र व प्रभावी

न्यायिक व्यवस्था के द्वारा लागू की जाती है तथा इस में अधिकाधिक भ्रष्टाचार का अभाव होता है।

- एक नीति संबंधी वातावरण, जो आर्थिक विकास को सरल बनाये तथा गरीबी में कमी से संबंधित हो। इसके अंतर्गत व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा वित्तिय नीतियों, बजट संबंधी संस्थायें, निजी क्षेत्र भी सम्मिलित हो।

- जनता द्वारा पर्याप्त लागत (शिक्षा व स्वास्थ्य पर सार्वजनिक व्यय के द्वारा) व आधारभूत संरचना में विभिन्न क्षेत्रों के सार्वजनिक व्यय का सही बटवारा हो।

- वहन करने योग्य तथा सुरक्षित नेट के द्वारा असुरक्षित की सुरक्षा व यथायोग्य गरीबी के पक्ष में सार्वजनिक व्यय पर बल देना।

- पर्यावरण की सुरक्षा जो यह आशवस्त करे कि आर्थिक विकास पर्यावरणीय क्षरण न करे। नीति निर्माता, षोद्यार्थी तथा अंतर्राष्ट्रीय संरचनाएँ सुशासन की संकल्पना करते हैं, तथा आधारभूत विशेषताओं को स्वीकार करते हैं। इनमें शामिल हैं:

- **सहभागिता (Participation)** : इसे सुशासन का केन्द्र भाग माना जाता है। सरकार के लिए यह आवश्यक है कि निर्णय निर्माण प्रक्रिया, सुस्पष्टता तथा हितों के प्रतिनिधित्व के प्रति नागरिकों के अपेक्षित स्वतंत्रता को सुनिश्चित करे, जो नीतियों व कार्यक्रमो में परिलक्षित करता है। सहभागिता स्वतंत्रता, आत्मविश्वास, स्वायत्ता व नागरिकों के आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देता है। यह उनको निर्णय व कार्यों को प्रभावित करता है जो उन पर शासन करता है। यह नीतियों की प्रतिक्रियात्मकता को प्रोत्साहित करता है व हितग्रहियों की आवश्यकता को बढ़ाता है।

- **विधि का शासन (Rule of Law)** : शासन का तात्पर्य शक्ति का विधिक स्वेच्छाचारी उपयोग नहीं है। किसी भी शासन के प्रभावी होने के लिए सही विधिक ढाँचा आवश्यक है। स्वतंत्र न्यायपालिका, जो कि लोगों में आत्मविश्वास ला सके व उचित विधि प्रवर्तन व्यवस्था का सहयोग भी आवश्यक है।

- **पारदर्शिता (Transparency)** : यह संचार के उन्मुक्त प्रवाह की प्राक्कल्पना पर आधारित है एवं उसकी उपलब्धता उनके लिए है जो कि प्रशासन की प्रक्रियाओं के निर्णयों से प्रभावित है। सूचना बोधगम्य होनी चाहिए तथा सूचना से जुडे लोगों के लिए प्रासंगिक होनी चाहिए। लोगों के लिए सूचना के सीमित प्रावधान उन्हें सार्वजनिक क्षेत्र व गैर सरकारी क्षेत्र की गतिधियों को समाविष्ट व निरीक्षण करने के लिए सक्षम बनाता है।

- **प्रतिक्रियात्मकता (Responsiveness)** : पूर्व की प्रशासकीय मशीनरी सभी हिस्सेदारो को अपने विस्तार क्षेत्र में लाने मं असफल रहा है। वर्तमान में संस्थाओं के प्रति अधिक उत्तरदायी है और वे उनके निर्णयो से प्रभावित होते हैं।

- **साम्यता (Equity)** : चूंकि प्रशासनिक ढाँचा व मशीनरी का लक्ष्य सहभागिता है, अतः निष्पक्षता को बढ़ावा देना जरूरी है। एक समाज की समृद्धि व विकास इस बात पर निर्भर करता है कि सभी सदस्यों की हिस्सेदारी व भूमिका उसमें है व मुख्यधारा की गतिविधियों से विलग नहीं है।

- **प्रभावी तथा दक्षता (Effectiveness and Efficiency)** : सामाजिक आवश्यकताओं व मांगों के साथ संसाधनों के सामजस्यपूर्ण उपयोग में प्रभावकारी व दक्षता का लक्ष्य सुशासन है, जो कि नवीन लोक प्रबंधन के समकक्ष है। परिणाम निर्देशन की आवश्यकता प्राथमिकता है।

- **उत्तरदायित्व (Accountability)** : स्थापित नियमों के हनन को रोकने के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करना होगा। इसके अंतर्गत राजनीतिज्ञों प्रशासको, अन्य सरकारी, गैर-सरकारी संगठन तथा निजी क्षेत्रों की गतिविधियों का उत्तरदायित्व शामिल है।

- **पूर्वानुमान (Predictability)** : इस से तात्पर्य स्पष्ट कानून व नियम से है, जो कि समाज व अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करते हैं।

UNDP (सयुंक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम) के गर्वनेंस फार सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलेपमेंट– Governance for Sustainable Human Development, 1997) की कार्यशाला में सुशासन की मुख्य विशेषताओं की व्याख्या की गई थी। इसके अंतर्गत :

- सहभागिता की प्रकृति
- लोगों के प्रति संवेदनशीलता
- शासन की विधियों व संसाधनों के विकास की क्षमता
- विधि के शासन का संचालन
- सक्षम, सरलीकृत व व्यवस्थित न कि अन्य का नियंत्रण
- सेवा अनुकूलन
- सत्तता
- लोगों द्वारा स्वीकृत
- निष्पक्षता व समानता को प्रोत्साहन
- लिंग समानता को बढ़ावा देना
- उत्तरदायी (सोभान–Sobhan, 1998)

बोवार्ड व लोफलर (Bovaird and Loffler, 2003) ने सुशासन की दस विशेषताएँ बताई है, जिसकी पुनरावृति साहित्य व राजनीति दोनों में तथा बहस के विषय के रूप में अक्सर होती है ये हैं :

- नागरिक अनुबंध (Citizens' Engagement)
- उत्तरदायित्व
- समानता की कार्य सूची (Equality Agenda) व सामाजिक समावेशन (लिंग प्रजातीयता, उम्र, धर्म आदि)
- नैतिक व इमानदार व्यवहार
- साम्यता (सही प्रक्रिया व उचित प्रक्रिया)
- वैश्विक परिवेश में प्रतिस्पर्द्धा करने में सक्षम होना
- भागीदारी में प्रभावी रूप से कार्य करने की क्षमता
- निरंतरता
- विधि के शासन के लिए सम्मान

सुशासन का लक्ष्य

- नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना
- शासन की दक्षता व प्रभाव को परिवर्धित करना
- संस्था की वैधानिकता व विश्वसनीयता को स्थापित करना
- सूचना व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को अक्षुण्ण (Interface) रखना
- नागरिक अनुकूल व नागरिक सहयोग शासन की व्यवस्था करना
- उत्तरदायित्व का आश्वासन
- नागरिक सरकार सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सूचना तकनीकी सेवा का उपयोग करना
- कर्मचारियों की उपयोगिता को बढ़ावा देना
- राज्य, बाजार व नागरिक समाज जैसे संगठनों में संगठनात्मक बहुवाद को प्रशासन के लिए बढ़ावा देना।

सुशासन का लक्ष्य अर्थव्यवस्था की प्रभावी प्रबंधन, वित्तीय संसाधन तथा लोकसेवा की प्राप्ति है। यह एक वृह्द सुधारवादी योजना है, जो सरकार को और अधिक जिम्मेदार, दक्ष, लोकतांत्रिक नियंत्रित निजी क्षेत्र , नागरिक समाज की संस्थाओं को मजबूत बनाना चाहती है। सुशासन शासन का गुणात्मक आयाम है। एक प्रशासकीय व्यवस्था तभी उचित व प्रभावी समझी जाएगी जब सभी सहभागी संस्थाएं शासकीय कार्यों, गतिविधियों व संस्थाओं में भागीदारी करे व विकेन्द्रीकरण, सहभागी व उत्तरदायित्व पर बल दें। सुशासन नवीन लोक प्रबंधन के दक्षता व प्रशासन के उत्तरदायित्व संबंध का मिलाजुला रूप है।

बोध प्रश्न 1

नोटः 1) अपने उत्तरों के लिए नीचे दिए स्थान का प्रयोग कीजिए।

2) इकाई के अंत में दिए उत्तरों से अपने उत्तर मिलाइए।

1) शासन की अवधारणा से आप क्या समझते हैं?

....

....

....

....

....

2) सुशासन की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए।

....

....

....

....

....

15.5 सुशासन से आगे

शासन व सुशासन की अवधारणा के उदय ने कई बहसों को प्रारंभ किया है। यह एक अनवरत प्रक्रिया है, जिसमें कई कर्ता व संस्थाएं शामिल होती है। यह पारंपरिक विचारों की मानसिकता में परिवर्तन पर बल देता है, जो कि संस्थापक सुधारों के लिए नए विचारों का उपयोग करना चाहते हैं। अत : यह वर्तमान के संस्थात्मक प्रयासों व प्रक्रियाओं को नए स्वरूप में परिवर्तित करने के लिए एक वृहद् आयोजन है। हर देश का एक निश्चित सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक परिवेश है। अत : शासन की योजनाओं का पालन करना एवं ऐतिहासिक व सांस्कृतिक भिन्नताओं का संज्ञान न लेना, लाभ को विपरीत दिशा में ले जा सकता है।

दक्षिण एशिया में मानव विकास पर एक रिपोर्ट (The Report on Human Development in South Asia,1999) ने मानवीय शासन को एक नई दिशा दी है। रिपोर्ट के अनुसार, दक्षिण एशिया की मानवीय अभाव की विशाल स्थिति केवल आर्थिक कारणों के कारण ही नहीं है। सामाजिक व राजनीतिक कारक भी ऐसी स्थिति के लिए बराबर के जिम्मेदार हैं। ऐसा अनुभव है कि विकास का अंतिम लक्ष्य मानवीय क्षमता का निर्माण तथा मानवीय चयन को वृहद् बनाना है, जिससे एक ऐसा सुरक्षित वातावरण का निर्माण हो, जहाँ नागरिक सम्मान व समानता के साथ निवास करते हो। यह मानवीय शासन है, जहाँ बेहतर राजनीतिक, आर्थिक व नागरिक शासन पर बल दिया जाता है।

समय के साथ कुछ सिद्धांतों का उदय हुआ जो विभिन्न अभिविन्यास/दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। शासन के प्रकार व सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक परिवेश के मध्य अंतसंबंध स्थापित करने का ''बेहतर शासन'' का प्रतिमान (Good enough Governance) ग्रिनडल (Grindle, 2004) द्वारा किया गया। इसके अनुसार, इससे बेहतर शासन का कोई और प्रतिमान नहीं है। ग्रिनडल ने तर्क दिया कि सुशासन का एजेंडा अव्यवहारिक रूप से लंबा है तथा क्या आवश्यक है और क्या नहीं, क्या पूर्व में आएगा तथा बाद में क्या, कम अवधि में व ज्यादा अवधि में क्या प्राप्त किया जा सकता है, क्या नहीं पर अधिक निर्देश नहीं देता। अतः उन्होंने ''बेहतरीन शासन'' की चर्चा की, जो अल्पतम स्वीकार्य सरकार की दषा, नागरिक समाज के कार्यों व उपलब्धि, जो कि आर्थिक व राजनीतिक विकास को बाधित नहीं करती एवं गरीबी निवारण व उन्मूलन की पहल को स्वीकृति प्रदान करता है। मुद्रा, समय, ज्ञान एवं मानव व संगठनात्मक क्षमता के लिए उपलब्ध संसाधनों के अंतर्गत ही बेहतर शासन के बेहतरीन तरीके ढूंढना आवश्यक है।

शासन के कार्यसूची (Agenda) में गरीबी उन्मूलन उपाए, सामाजिक सुरक्षित इंटरनेट, भ्रष्टाचार निरोधी उपाए के साथ ही इस समझ में वृद्धि हो रही है कि क्रियान्वयन का संज्ञान लिया जाए। हेल्ड (Held *et. al*, 2005) ने इसे ''संवर्धित वांशिगटन सहमति'' (Augmented Washington Consensus) माना है। इस नए प्रतिमान (Model) का लक्ष्य राज्य, अर्थव्यवस्था व नागरिक समाज के मध्य संबंध स्थापित करना है। शासन की नवीन सोच राजनीति, सामाजिक, आर्थिक आयामों को एकीकृत करना है, ताकि विकास संपोषित हो सके। एक बेहतरीन शासन व्यवस्था में संपूर्ण लोक नीति निरूपण व कार्यान्वयन एवं औपचारिक व अनौपचारिक कर्ता शामिल होते हैं, जो पारदर्शी, उत्तरदायी, लोकतांत्रिक व सहभागी तरीके से कार्य करते हैं।

15.6 सुशासन : मुद्दे व चुनौतियाँ

जैसे की पूर्व में चर्चा की गई है, शासन व सुशासन वर्तमान के संदर्भ में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इसका उद्देश्य नागरिकों का अधिकतम कल्याण है। इसमें सरकार, निजी क्षेत्र व जनता के समुदायों या नागरिक समाज को शामिल किया जाता है। शासन प्रक्रिया के समक्ष महत्वपूर्ण चुनौतियाँ एक ऐसे ढाँचे या व्यवस्था का निर्माण है, जो इन तीन घटकों के मध्य उपर्युक्त संतुलन को प्रोत्साहित करे। सुशासन एक सतत् प्रक्रिया है,जो कि अनवरत चलनी चाहिए, परंतु यह एक बहुत बड़ा काम है, जिसमें बहुआयामी योजना शामिल है।

सुशासन के लिए शामिल महत्वपूर्ण मुद्दे व चुनौतियाँ है–

- **शासन की संस्थाओं को सशक्त बनाना–**

  भारत में संसद सर्वोच्य प्रतिनिधित्व संस्था है। राजनीतिक प्रतिनिधि, निर्वाचकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। कई बार विभिन्न मंचों पर भागीदारी की गुणात्मकता में गिरावट तथा कार्यवाहियों पर चिंता जाहिर की है। अतः संसदात्मक कार्यों के उचित प्रक्रिया व कार्यवाही की आवश्यकता है एवं परिवर्तित समय में संसद को गतिशील संस्था भी बनाना है।

- सिविल सेवा तथा नौकरशाही की कार्यप्रणाली को बेहतर बनाना आखिरकार स्थाई कार्यपालिका ही नीति कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होती है।जिम्मेदार सिविल सेवा को विकसित करने की आवश्यकता है, जो पेशेवर, उर्जावान हो तथा लोगों की आवश्यकता की पूर्ति करते हो।

- स्वंतत्र व उत्तरदायी न्यायपालिका की स्थापना से जनता को आश्वस्त करना–न्यायपालिका को विधि का शासन तथा सामाजिक न्याय की स्थापना का प्रभावी साधन है।

- निजी क्षेत्रों को उत्तरदायी बनाना–यह संभव है अगर व्यवसाय सुचारू रूप से नियमों के आधार पर चले तथा उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करे।

- नागरिकों को उनके अधिकारों व कर्तव्यों के लिए शिक्षित करना–विकासात्मक गतिविधियों में सहभागी बनाकर उन्हें शिक्षित किया जा सकता है।

- सुशासन में राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक क्षेत्रों के प्रमुख मुद्दो पर ध्यान देना आवश्यक है–राजनीतिक शासन को सशक्त बनाने के लिए विकेन्द्रीत उपायो से, नागरिकों के प्रति निर्वाचित प्रतिनिधियो को उत्तरदायी व जिम्मेदार बनाना, उनकी क्षमताओं को निक्षा, जागरूकता, प्रशिक्षण द्वारा बढ़ाना, नियमित व सही चुनाव कराना, निष्पष न्यायपालिका तथा सिविल सेवा की कार्यप्रणाली को बेहतर बनाना।

- आर्थिक प्रशासन को अधिक महत्व मिलना चाहिए–शिक्षा, स्वस्थ्य, गृह, उचित कराधान तथा अनुवृति (Subsidy) व्यवस्था जैसे सामाजिक क्षेत्रों के प्रमुख विषयों के लिए पर्याप्त बजट प्रावधान होने चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि सरकार निजी उपक्रम के विकास को उचित व्यवसायिक गतिविधियों, संतुलित आर्थिक वातावरण का निर्माण, उचित नियामक ढाँचा, कर्मचारी, उपभोक्ता व वृहद रूप में समाज के हितों की रक्षा के द्वारा बढ़ावा दे।

- नागरिक शासन के अंतर्गत लोगों द्वारा स्वंय की पहल से काम लेना शामिल है। उनके जीवन को शासित करने की क्षमता पर बढ़ोतरी पर अधिक ध्यान केन्द्रित करना चाहिए, जिससे जागरूकता बढ़े तथा वे लोकतांत्रिक शासन प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका के प्रयास करें।

सुशासन के मुददे् व चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार के तीनो अंग यथा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका व न्यायपालिका की प्रभावी कार्यप्रणाली हो एवं विभिन्न अंगो के मध्य उचित संबंधों का निर्माण हो। शासन को संसदात्मक सर्वोच्चता एवं स्वतंत्र न्यायपालिका के मध्य संतुलन बनाना पड़ता है। जैसे कि शासन प्रक्रिया में राज्य, निजी क्षेत्र व नागरिक समाज की अहम भूमिका होती है, इन अंगो को भूमिका व उत्तरदायित्व सौपनें की आवश्यकता है, जिससे वे लोगों से संबंधित विकास गतिविधियों को कार्यान्वित कर सके।

शासन एक प्रतिमान है, साथ ही अनेक संस्थाओं, हिस्सेदारों व उनके मध्य संबंधों से संबंधित प्रक्रिया है। सुशासन प्रक्रिया को सरल बनाने, नीति संबंधित ढाँचे, उत्तरदायित्व, दक्षता व पारदर्शिता पर आधारित होता है, जो सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक व नागरिक शासन से संधित गतिविधियों को बढ़ावा देता है। यह एक सतत् प्रक्रिया है, जिस के द्वारा द्वदांत्मक व विविध हित अनुग्रहकारी, सहयोगात्मक कार्यों को प्रोत्साहित किया जाता है व औपचारिक व अनौपचारिक संस्थाओ को जनहित की अपेक्षाओ के लिए सराहा जाता है। भारत ने नागरिक घोषणापत्र के क्रियान्वयन, लोक शिकायत के निवारण, सूचना का अधिकार जब भागीदारी आदि इस दिशा की ओर किए जाने वाले कार्य हैं।

बोध प्रश्न 2

नोटः 1) अपने उत्तरों के लिए नीचे दिए स्थान का प्रयोग कीजिए।

2) इकाई के अंत में दिए उत्तरों से अपने उत्तर मिलाइए।

1) बेहतरीन शासन के प्रतिमान (माडल) की व्याख्या कीजिए।

....

....

....

....

....

2) सुशासन से संबंधित प्रमुख मुद्दों व चुनौतियों का वर्णन कीजिए।

....

....

....

....

....

15.7 निष्कर्ष

सरकार से शासन तक के परिवर्तन के अंतर्गत उच्चस्थ राजनीतिक व्यवस्था से अनेक एजेन्सियों, संस्थाओं व व्यवस्थाओ में परस्पर संबंध आते हैं। लोक निर्णय निर्माण में अनेक कर्ताओ की भूमिका को पहचानने के कारण इसने बिना किसी संशय के लोक प्रशासन के क्षेत्र को प्रसारित किया है। 1980 के दशक में लोक प्रशासन को दिए गए अत्याधिक प्रबंधक के प्रभाव व महत्व ने लोकतांत्रिक राजनीति को प्रभावित किया है। शासन व सुशासन के साथ ही पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, विधि का शासन, नैतिकता , सत्यनिष्ठा ने समय के साथ सर्वोच्चता हासिल कर ली है, एवं जो लोक प्रशासन के विभिन्न उपागमो की

चर्चा करते हैं। इस इकाई में शासन के अर्थ की चर्चा की गई है। इसमें शासन से सुशासन में परिवर्तन का परीक्षण किया गया है। इसमें सुशासन की विशेषताओं व शिक्षा का वर्णन किया गया है। इस इकाई में सुशासन के स्थापित होने में आने वाली चुनौतियों का भी वर्णन किया गया है।

15.8 शब्दावली

नागरिक समाज (Civil Society) : यह गैर-सरकारी संगठनों व संस्थाओं का कुल योग है, जो नागरिकों के हितों व इच्छाओं को व्यक्त करता है। इसे नागरिकों का समुदाय माना गया है, जो समान हितों व सामूहिक गतिविधियों से जुड़े हुए है।

नागरिक घोषणापत्र (Citizens' Charter) : 1991 में ब्रिटेन में नागरिक घोषणापत्र प्रशासन को अधिक उत्तरदायी, पारदर्शी, दक्ष व सुलभ बनाने के लिए स्थापित हुआ है। धोशणापत्र का मुख्य उद्‌देश्य जनता को सेवाएं उपलब्ध कराने वाली लोक संस्थाओं से संबंधित उपयुक्त जानकारी उपलब्ध कराना था। चूंकि नागरिकों का अधिकार है उत्तरदायित्व व सरकारी विभागों द्वारा प्राप्त सेवाओं की मांग करना, अतः घोषणापत्र अबाध्य गुणात्मक बेहतरीन सेवा जनता को उपलब्ध कराने का प्रयास करता है।

समाज सुरक्षा नेट (Social Safety Nets) : इनका संबंध राज्य व अन्य संस्थाओं द्वारा सेवाएं उपलब्ध कराना है, जिसका प्रारंभिक उद्‌देश्य गरीबी कम करना है।

वाशिंगटन सहमति (Washington Consensus) : जान विलियमसन (John Williamson) द्वारा 1989 में इस शब्दावली का उपयोग किया गया है जो कि वांशिगटन में स्थापित संस्थाओं द्वारा नीति संबंधी मशविरा उपलब्ध कराती है जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोश, लैटिन अमरीका के देशों के लिए विश्व बैंक! यह कार्पोरेट शासन, लचीला मजदूर बाजार, व्यापार समझौता, भ्रष्टाचार निरोधी उपकरण आदि।

15.9 संदर्भ लेख

Arora, R. K. (2004). Public Administration, Resilience and Rejuvenation.In *Public Administration Fresh Perspectives*, Jaipur, India: Aalekh Publishers.

Bhattacharya, M. and Chakraborty, B. (2003). *Public Administration: A Reader.* New Delhi, India: Oxford University Press.

Bhattacharya, M. (2011) (Revised). *New Horizons of Public Administration,* New Delhi, India: Jawahar Publications.

Bovaird,T and Loffler, E (2003). Evaluating the Quality of Public Governance:Indicators,Modelsand Methodologies. *International Review of Administrative Sciences*: Vol.69.

Craig, D. and Porter, D (2006).*Development Beyond Neoliberalism? Governance, Poverty Reduction and Political Economy*, New York, U.S: Routledge.

Farazmand, A. (2002).Globalisation and Public Administration. In Peter Kobrak (Ed.), *The Political Environment of Public Management,* New York, U.S: Longman.

Federickson G., "Whatever Happened to Public Administration, Governance, Governance Everywhere" www.rhul.ac.uk/mgt/nwsandevents/seminars.

Held, D *et. al*. (Eds.) (2005). *Debating Globalisation,*Cambridge, U.K: Polity Press.

Medury, U. (2010). *Public Administration in the Globalisation Era: The New Public ManagementPerspective* . New Delhi, India: Orient Blackswan.

Rhodes, R.A.W.(1997), *Understanding Governance Policy Networks, Governance, Reflexivity and Accountability,* USA*:* Open University Press.

Singh, K. (2003).'Aid and Good Governance:' A Discussion Paper on The Reality of Aid. (Retrieved from www.realityofand.org).

Stoker, G. (1998). "Governance as Theory: Five Propositions", *International Social Science Journal*, Vol. 50, No. 1: 17-28.

Ul Haq, M. (1999). *Human Development in South: Asia The Crisis of Governance,* Human Development Centre. Oxford: Oxford University Press.

UNDP (1997*). Good Governance and Sustainable Human Development*, *A Policy Document.* (Retrieved from http://magnet.undp.org/policy/chapter1.htm).

World Bank (1989) *Sub-Saharan Africa: from Crisis to Sustainable Growth: A Long-term Perspective Study,* Washington DC.

World Bank (1992).*Governance and Development,* Washington DC.

15.10 बोध प्रश्नों के उत्तर

बोध प्रश्न 1

आपके उत्तर में निम्न को शामिल होना चाहिए :

1) शासन शब्द का उद्भव ग्रीक शब्द काइर्बनान से हुआ जिसका तात्पर्य संचालन है।

   - यह सरकार से बड़ा (बृह्द) है तथा इस के अंतर्गत नीति निर्माण व क्रियान्वयन की प्रक्रिया व कार्यप्रणाली शामिल है।
   - शासन वह प्रक्रिया है, जिसके द्वारा राज्य की नीतियाँ जो जनता को प्रभावित करती है, उनका क्रियान्वयन होता है।
   - यह सरकार, निजी क्षेत्र व समुदायो की नीतियों व कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के प्रयासों पर जोर देती है।

2) आपके उत्तर में निम्न को शामिल होना चाहिए।

   - सुशासन की विशेषताओं में निम्न शामिल है :

     अ) सहभागिता

     ब) विधि का शासन

     स) पारदर्शिता

     द) प्रतिसंवेदनशीलता

     च) निष्पक्षता

     छ) प्रभावकारिता व दक्षता

     ज) उत्तरदायित्व

     झ) पूर्वानुमान

बोध अभ्यास 2

1) आपके उत्तर में निम्न को शामिल होना चाहिए :

- .मैरीइल. एस. ग्रिन्डल (Merryl S. Grindle) के द्वारा बेहतरीन शासन का माडल प्रदान किया गया।
- यह शासन के प्रकारों तथा सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक परिवेश के मध्य अंत : संबंध स्थापित करता है।
- सुशासन का एजेंडा काफी व्यापक है अत : कम स्वीकृत शासन की दशाओ को प्रस्तावित किया गया है।
- प्रत्येक राष्ट्र को समय, धन, ज्ञान, मानवीय व संगठनात्मक क्षमताओं के उपलब्ध संसाधनों के ढाँचे के अनुसार शासन कार्यक्रम (एजेंडा) निर्धारित करना चाहिए।

2) आपके उत्तर में निम्न को शामिल होना चाहिए:

- शासन की संस्थाओं, जिसके अंतर्गत संसद व न्यायपालिका हो को सशक्त करना।
- सिविल सेवा व नौकशाही की कार्यप्रणाली को बेहतर करना।
- निजी क्षेत्र की उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करना।
- नागरिकों को उनके अधिकारों व कर्तव्यों के लिए शिक्षित करना।
- राजनैतिक, आर्थिक व नागरिक शासन को मजबूती प्रदान करना।

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY